

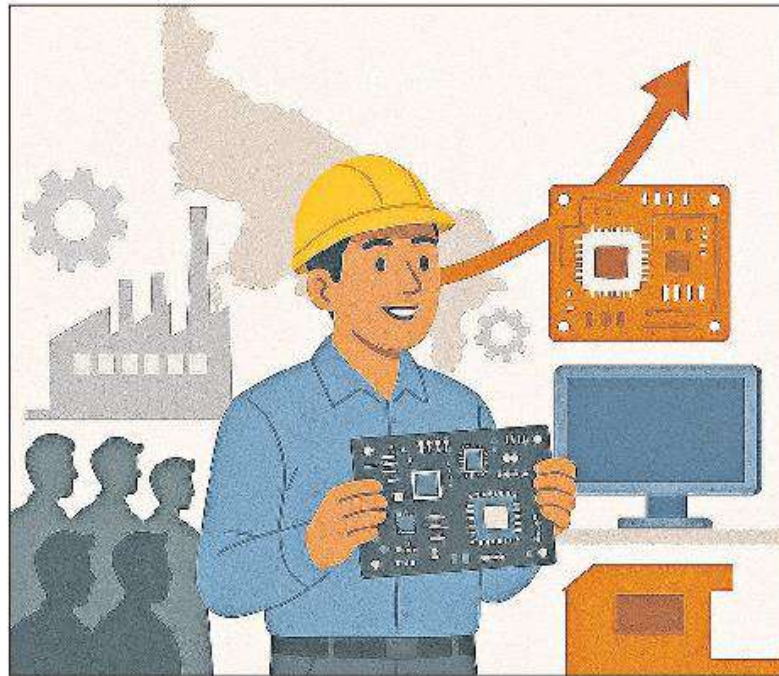
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 50 हजार को मिलेगा रोजगार

मार्च तक 25 नए प्रस्ताव आने की संभावना, होगा 5500 करोड़ का निवेश

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए औद्योगिक निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस कर रही है, जिससे 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया हो सकेंगे। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मार्च 2026 तक करीब 25 नए प्रस्ताव सामने आने की संभावना है, जिनका कुल निवेश अनुमानित 5,500 करोड़ रुपये होगा। इसमें प्रदेश में मौजूदा समय में काम कर रही कई बड़ी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का विस्तार करने पर भी विचार कर रही हैं। राज्य सरकार की योजना के साथ-साथ भारत सरकार की ईसीएमएस (इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम) के तहत भी अब तक राज्य सरकार को 22 निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके अलावा भूमि उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में 20 और निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को मिल सकते हैं।

सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी दो नई परियोजनाओं को मिल सकती है मंजूरी : इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ-साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी राज्य सरकार को दो नई



AI Image

अब तक की प्रगति

- दिसंबर 2024 तक 22 नए LOC जारी किए गए, जिनमें 1,928.99 करोड़ का निवेश और 8,941 रोजगार सृजन का अनुमान है।
- जनवरी 2025 में 13 नए LOC जारी हुए, जिनमें 1,363.64 करोड़ का निवेश और 4,200 रोजगार की संभावना है।
- कुल मिलाकर, 2020 से अब तक 67 LOC जारी किए जा चुके हैं, जिनसे 15,477 करोड़ का निवेश और 1,48,710 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

परियोजनाएं यूपी के खाते में आ सकती हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में यूपी की एक परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ये सेमीकंडक्टर यूनिट यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में लगाई जा रही है। इसके अलावा इस सेक्टर के दो प्रोजेक्ट्स को केंद्र की अनुमति दिसंबर अंत तक मिलने की उम्मीद है। यूपी में वामा सुंदरी इनवेस्टमेंट के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में फॉक्सकॉन भी साथ है। इस फैसिलिटी को यमुना एक्सप्रेस-वे के

साथ विकसित किया जाएगा और इस पर 3706 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्रों के खाली पड़े प्लॉट्स पर लगेंगी यूनिट : राज्य सरकार को मिल रहे निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीनों की उपलब्धता है। इसके लिए भी औद्योगिक विकास विभाग ने काम शुरू कर दिया है। औद्योगिक विकास विभाग औद्योगिक क्षेत्रों के

खाली प्लॉटों का सर्वेक्षण करवा रहा है। इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 प्रतिशत से अधिक प्लॉट खाली हैं। अब राज्य सरकार इन प्लॉट्स का आवंटन रद्द करके नई इंडस्ट्री को आवंटित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सिक यूनिट्स की जमीनों पर भी इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की योजना है। प्रदेश में कई कताई मिले बंद हो गई हैं, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे।